(b) Information is being compiled & will be laid on the table of the House.

(c) under Section 55 of the MRTP Act, decisions of the MRTP Commission are appealable to the Supreme Court of India within 60 days from the date of the order on one or more of the grounds specified in Section 100 of the Code of Civil Procedure. Supreme Court had set aside the decision of the MRTP Commission on 2-5-1989 in the case of M/s Lakhan Pal National Limited. Supreme Court and several High Court have also granted interim stay of the operation of the orders of MRTP-Commission in some cases.

(d) The MRTP Act was amended with effect from 27-9-1991 and the relevant provisions have been strengthened further empowering the Commission to effectively dealing with Monopolistic, Restrictive and Unfair Trade Practices. The Commission has been given powers to punish for contempt of its Orders. The Government have also extended the provisions of the MRTP Act to the Public Sector Undertakings.

एक समान सिविल संहिता

1727. **डा० बापू कालदाते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) सभी नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता प्रारंभ करने से अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधि में परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाएगा। सरकार की बराबर यह नीति रही है कि वह तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि इन्हीं समुदायों की ओर से परिवर्तन के लिए कोई पहल अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि में न ली जाए।

चुनावों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की सिफारिशें

1728. **डा० बापू कालदाते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने चुनावों के संदर्भ में हाल ही में सरकार को कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) सरकार द्वारा निर्वाचन सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रस्तावों के साथ-साथ कतिपय अन्य प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है।

विवरण

निर्वाचन सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

1. निर्वाचन आयोग, एक सदस्यीय निकाय होना चाहिए।
2. निर्वाचन आयोग का एक स्वतन्त्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग का व्यय "भारतीय" होना चाहिए न कि "दत्तमत"।
3. निर्वाचक नामावलियों को प्रत्येक अनुकल्पी वर्ष में गहन रूप से पुनरी-